अनुदान योजना

[स्रोत : इंडयिन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सबवेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में घर खरीदने वालों को राहत प्रदान की है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करें जिन्हें अपने फ्लैटों का आधिपत्य नहीं मिला है।
- **सबवेंशन स्कीम:**
    - रियिल एस्टेट में सबवेंशन स्कीम में **खरीदार, बैंकर और डेवलपर के बीच त्रपिक्षीय समझौता** होता है।
    - खरीदार **5-20% अग्रमि भुगतान** करता है, जबकि बैंक डेवलपर को बाकी राशि उधार देता है।
    - डेवलपर तब तक ऋण ब्याज का भुगतान करता है जब तक खरीदार कब्ज़ा नहीं ले लेता, जिसके बाद खरीदार की EMI शुरू होती है।
    - यह योजना डेवलपर्स के लिये बिक्री को बढ़ावा देती है और खरीदारों के लिये EMI भुगतान में देरी करती है।
    - हालाँकि, वर्तमान मामले में कई बिल्डर से इन भुगतानों में चूक हुई है।
- **सब्सिडी:**
    - सब्सिडी **सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा उपभोक्ता के लिये किसी उत्पाद या सेवा की लागत को कम करने के लिये दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता** है।
    - इससे उपभोक्ता के लिये उत्पाद या सेवा की कीमत में कमी आती है। उदाहरण के लिये, खाद्यान्न, उर्वरक या ईंधन पर सरकारी सब्सिडी।

और पढ़ें: [ब्याज सहायता योजना](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/subvention-scheme-2